



PRESS RELEASE

DEEPFAKES AND MISINFORMATION POSE SERIOUS THREATS TO DEMOCRACY: LOK SABHA SPEAKER/डीपफेक और भ्रामक सूचना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है: लोक सभा अध्यक्ष

...

AI MUST BE USED TO STRENGTHEN TRUTH AND CREDIBILITY, NOT TO DISTORT OR SUPPRESS FACTS: LOK SABHA SPEAKER/एआई का उपयोग सत्य और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने के लिए हो, तथ्यों को विकृत या दबाने के लिए नहीं: लोक सभा अध्यक्ष

...

AI HAS THE POTENTIAL TO MAKE DEMOCRACY MORE TRANSPARENT, ACCOUNTABLE AND CITIZEN-CENTRIC: LOK SABHA SPEAKER/एआई में लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की क्षमता है: लोक सभा अध्यक्ष

...

DIGITAL PARLIAMENT AND AI ARE STRENGTHENING DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY: LOK SABHA SPEAKER/डिजिटल संसद और एआई लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुदृढ़ कर रहे हैं: लोक सभा अध्यक्ष

...

INDIA'S DIGITAL INFRASTRUCTURE A MODEL FOR THE WORLD: LOK SABHA SPEAKER/भारत की डिजिटल अवसंरचना विश्व के लिए एक आदर्श: लोक सभा अध्यक्ष

...

AI TO ACCELERATE 'VIKSIT BHARAT 2047' IN EDUCATION, HEALTHCARE AND AGRICULTURE: LOK SABHA SPEAKER/शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में 'विकसित भारत 2047' को गति देगा एआई: लोक सभा अध्यक्ष

...

LOK SABHA SPEAKER ADDRESSES "AI FOR DEMOCRACY" SPECIAL SESSION AT INDIA AI IMPACT SUMMIT/लोक सभा अध्यक्ष ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में "एआई फॉर डेमोक्रेसी" पर विशेष सत्र को संबोधित किया

...

New Delhi; 20 February, 2026: Lok Sabha Speaker today drew attention to the growing challenges posed by deepfakes and misinformation. Describing them as serious threats to democracy, he emphasized that Artificial Intelligence (AI) must be used to strengthen truth and credibility, not to distort or suppress facts. He

stressed the need for developing robust safeguards alongside technological advancements to protect democratic discourse from manipulation and confusion.

<https://x.com/ombirlakota/status/2024825172730216736>

Addressing the special session on the theme “AI for Democracy” at the India AI Impact Summit being held at Bharat Mandapam today, Shri Birla noted that AI has the potential to make democracy more transparent, accountable and citizen-centric. He stressed that the nation’s guiding principle has always been “Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya”—for the welfare and happiness of all. India, he noted, works with the spirit of global well-being, rooted in its enduring civilizational values.

Highlighting the transformative role of technology in legislative functioning, the Speaker observed that AI is emerging as a significant tool for strengthening democratic institutions. He was happy to note that initiatives such as “Digital Parliament” are simplifying communication between citizens and Parliament, bridging digital and information divide in a diverse country like India. He informed that under the Digital Parliament initiative, parliamentary proceedings have been made paperless, modern and environmentally sustainable. With the help of AI tools, thousands of hours of parliamentary debates and records have been systematically organized and made easily searchable and accessible to the public. This, he emphasized, enhances transparency and enables citizens to closely monitor the performance of their elected representatives, thereby increasing accountability.

Referring to India’s linguistic diversity, the Speaker underlined the importance of the “Sansad Bhashini” initiative, through which parliamentary debates are being made available in multiple regional languages using AI-enabled translation tools. Citizens across the country can now access and understand parliamentary discussions in their own languages, strengthening trust and participation in the democratic process.

The Speaker highlighted that the discussions during international parliamentary forums, including global engagements of presiding officers, have underscored the importance of aligning democratic institutions with modern technology. In this context, he noted that India’s innovations in leveraging AI for legislative efficiency have been widely appreciated as a global model. He added that AI tools and modern data systems are also helping Members of Parliament better understand the needs and aspirations of their constituencies, thereby enabling more informed and citizen-focused policymaking.

Shri Birla stated that India’s AI strategy is guided by the principle of inclusive development; and the use of AI in sectors such as education, healthcare and agriculture will accelerate the country’s journey towards the vision of “Viksit Bharat 2047.” By enhancing access to quality education, improving healthcare delivery systems and empowering farmers with data-driven solutions, AI can transform the lives of millions, particularly those in underserved and unorganized sectors. Shri Birla further stated that India’s digital infrastructure has become

exemplary for the world. With its scale, inclusivity and efficiency, India's digital public infrastructure is being studied and appreciated globally. He reiterated that India is committed to sharing its digital experiences and technological expertise with the international community for collective progress.

While advocating the adoption of AI, Shri Birla cautioned that technology cannot replace human sensitivity and ethical judgment. "AI is a means, not an end," he remarked, emphasizing that human values, democratic principles and ethical standards must remain paramount in the development and deployment of emerging technologies. He called for nurturing a generation of youth equipped not only with technological expertise but also with compassion and a strong moral foundation. He expressed confidence that deliberations at the "AI for Democracy" session would contribute meaningfully to shaping a future where technology and democratic values move forward together. He also hoped that the harmonious integration of innovation and civilizational ethos would pave the way for a strong, inclusive and developed India by 2047.

Several dignitaries including Minister for AI & Online Safety, UK; Deputy Speaker, Parliament of Hungary and Secretary-General, IPU also addressed the participants. The programme was jointly organized by Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and the Inter-Parliamentary Union.

नई दिल्ली; 20 फरवरी, 2026: लोक सभा अध्यक्ष ने आज डीपफेक और भ्रामक सूचना से उत्पन्न हो रही चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन्हें लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग सत्य और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि तथ्यों को विकृत या दबाने के लिए। उन्होंने लोकतांत्रिक विमर्श को भ्रम और दुष्प्रचार से सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ-साथ सुदृढ़ सुरक्षा उपाय विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

<https://x.com/ombirlakota/status/2024825172730216736>

आज भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के अंतर्गत "एआई फॉर डेमोक्रेसी" पर विशेष सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि एआई में लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का मार्गदर्शक सिद्धांत सदैव "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" रहा है और भारत अपने शाश्वत सभ्यतागत मूल्यों के अंतर्गत वैश्विक कल्याण की भावना के साथ कार्य करता है।

विधायी कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका का उल्लेख करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि एआई लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभर रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि "डिजिटल संसद" जैसी पहलें नागरिकों और संसद के बीच संवाद को सरल बना रही हैं तथा भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में डिजिटल और सूचना डिवाइड को पाट रही हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल संसद पहल के अंतर्गत संसदीय कार्यवाही को कागजरहित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। एआई उपकरणों की सहायता से हजारों घंटों की संसदीय बहसों और अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से संकलित कर आसानी से खोजने योग्य और सार्वजनिक रूप से सुलभ

बनाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ती है और नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यों की निकटता से निगरानी कर सकते हैं, जिससे जवाबदेही सुदृढ़ होती है।

भारत की भाषाई विविधता का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष ने “संसद भाषिणी” पहल के महत्व को रेखांकित किया, जिसके माध्यम से एआई आधारित अनुवाद उपकरणों की सहायता से संसदीय बहसों को अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देशभर के नागरिक अपनी भाषा में संसदीय चर्चाओं को समझ और उनसे जुड़ सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास और सहभागिता मजबूत होती है।

लोक सभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय संसदीय मंचों पर, विशेषकर पीठासीन अधिकारियों की वैश्विक सहभागिताओं के दौरान, लोकतांत्रिक संस्थाओं को आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ने के महत्व पर बल दिया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि विधायी दक्षता के लिए एआई के उपयोग में भारत के नवाचारों की विश्व स्तर पर सराहना की जा रही है। आधुनिक डेटा प्रणालियां संसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को बेहतर समझने में सहायता कर रही हैं, जिससे अधिक जन-केंद्रित नीति निर्माण संभव हो रहा है।

श्री बिरला ने कहा कि भारत की एआई रणनीति समावेशी विकास के सिद्धांत पर आधारित है; और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य की दिशा में देश की प्रगति को तीव्र करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाकर, स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी प्रणाली को सुदृढ़ कर तथा किसानों को डेटा-आधारित समाधान उपलब्ध कराकर एआई लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, विशेषकर वंचित और असंगठित क्षेत्रों में। उन्होंने आगे कहा कि भारत की डिजिटल अवसंरचना विश्व के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। अपने व्यापक स्वरूप, समावेशिता और दक्षता के कारण भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का वैश्विक स्तर पर अध्ययन और सराहना की जा रही है। उन्होंने दोहराया कि भारत सामूहिक प्रगति के लिए अपने डिजिटल अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एआई के उपयोग की वकालत करते हुए श्री बिरला ने यह भी चेताया कि प्रौद्योगिकी मानव संवेदनशीलता और नैतिक निर्णय का स्थान नहीं ले सकती। उन्होंने कहा, “एआई एक साधन है, साध्य नहीं,” और इस बात पर बल दिया कि उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग में मानवीय मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नैतिक मानकों को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। उन्होंने ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करने का आह्वान किया जो तकनीकी दक्षता के साथ-साथ करुणा और सुदृढ़ नैतिक आधार से भी संपन्न हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि “एआई फॉर डेमोक्रेसी” सत्र में हुए विचार-विमर्श भविष्य के निर्माण में सार्थक योगदान देंगे, जहां प्रौद्योगिकी और लोकतांत्रिक मूल्य साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि नवाचार और सभ्यतागत मूल्यों का समन्वित समागम वर्ष 2047 तक एक सशक्त, समावेशी और विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम के एआई एवं ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री श्री कनिष्क नारायण; हंगरी की संसद के उपाध्यक्ष श्री लाजोस ओलाह; तथा इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू)

के महासचिव श्री मार्टिन चुंगोंग सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।